



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 1989/आषाढ़ 5, 1911

No. 331]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 1989/ASADHA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आधिकारीकार्य विभाग)

अधिकृतना

नई दिल्ली, 26 जून, 1989

बीमा

भारतीय जीवन बीमा नियम विकास अधिकारी (सेवा के कुछ

निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989

सा.का.नि. 643 (अ) :—देशीय सरकार, जीवन बीमा नियम
अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2)
के खण्ड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) के पारा प्राप्त विविध विविध
का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा नियम के विकास अधिकारियों
के कारबाह नियैहत से संबंधित सेवा के कुछ निबंधनों और शर्तों का
विनियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, गर्थतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा नियम
विकास अधिकारी (सेवा के कुछ निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण)
नियम, 1989 है।

(2) इन नियमों में जो अन्यथा उपलब्धित है उसके सिवाय वे

1 अप्रैल, 1988 को प्रयृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएँ :

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा घोषित न हो,—

(क) "अधिनियम" से जीवन बीमा नियम अधिनियम, 1956 (1956
का 31) अभियेत है,

(ख) "तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक" से नियम 7 के उपनियम (1)
के स्पष्टीकरण के खण्ड (1) में उपलब्धित रीति में संगणित
अवधारणा के प्रयोजन के लिए किसी विकास अधिकारी को
लागू होने वाला वार्षिक पारिश्रमिक अभियेत है,

(ग) "वार्षिक पारिश्रमिक" से अभियेत है: मूल बेतन, विशेष बेतन,
व्यक्तिगत बेतन, महंगाई भस्ते, तथा अन्य सभी भस्ते और

सामने निरपेक्ष भागीदारी या अनुप्राप्त बोनम जो मूल्य निर्धारण वर्ष में विकास अधिकारी को देय या मिला है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यय भी है जो उस वर्ष के दौरान यात्रा, आवासीय, टेलीफोन, बीमा प्रीमियम तथा मोटर वाहन के संबंध में उसे निगम, द्वारा देय है या जिसकी वाबत निगम ने उसकी प्रतिपूर्ति की है जो निगम ने उपगत किया है, किन्तु इसके अन्तर्गत नियम 17 के अनुसार उसे संवत् प्रेरणा बोनस या प्रतिरिक्षित परिवहन सेवारी मता नहीं है,

(प) "मूल्य निर्धारण तारीख" से मिस्निलिखित अभिप्रेत है:—

(1) 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् नियुक्त किसी विकास अधिकारी के संबंध में,—

(अ) अपनी सेवा काल के प्रथम वर्ष में, उस मास का प्रथम दिन, जो उस मास के बाद आता है, जिसमें वह अपनी नियुक्ति की तारीख से बारह मास की सेवा पूरी करता है; और

(आ) अपने सेवाकाल के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में, पिछली मूल्य निर्धारण तारीख से बारह मास का सेवाकाल पूरा होने के बाद ठीक अगले मास का प्रथम दिन।

(2) 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व नियुक्त किसी विकास अधिकारी के संबंध में,—

(अ) 1 अप्रैल, 1988 से अपने सेवा काल के प्रथम वर्ष में,

(1) 1 अप्रैल, 1988, यदि वह 31 मार्च, 1988 को बारह मास की सेवा पूरी करता है, या

(2) उस मास का प्रथम दिन, जो उस मास के बाद आता है जिसमें वह उस तारीख से बारह मास की सेवा पूरी करता है जिसको उसकी प्रतिम वार्षिक वेतनवृद्धि भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीबूद्धि) नियम, 1960 के नियम 56 के उपनियम (2) के अनुसार ओदूपत तुर्ही थी (जारी नियमेंति की गई हो या नहीं) यदि उसने 1 मार्च, 1988 को बारह मास या उससे प्रतिक की सेवा पूरी कर ली थी; और

(आ) अपने सेवाकाल के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में, पिछली मूल्य निर्धारण तारीख से बारह मास का सेवाकाल पूरा होने के बाद ठीक अगले मास का प्रथम दिन;

(इ) "मूल्य निर्धारण वर्ष" से अभिप्रेत है, दो लगातार मूल्य निर्धारण तारीखों के बीच की प्रवधि और उपलब्ध (1) की मद (अ) के अनुसार अभिनिश्चित मूल्य निर्धारण तारीख से पहले पड़ने वाली बारह मास की प्रवधि, और उपलब्ध (अ) के उपलब्ध (2) की मद (अ) के अनुसार अभिनिश्चित मूल्य निर्धारण तारीख से पहले पड़ने वाली सेवा की बारह मास की प्रत्येक प्रवधि भी मूल्य निर्धारण वर्ष होगी;

(ब) "लागत अनुपात" से विकास अधिकारी के संबंध में वह अनुपात अभिप्रेत है जो किसी वर्ष में उसके वार्षिक पारिश्रमिक या उसके तर्थी वार्षिक पारिश्रमिक, यदि लागू होता हो, का उस वर्ष के आवेद्य प्रीमियम से है और ऐसे आवेद्य प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है;

(छ) "वेतन-हास" से एक या अधिक अवसरों पर वेतनभान में एक या अधिक प्रक्रमों द्वारा मूल वेतन में कमी करना अभिप्रेत है;

(ज) "विकास अधिकारी" से विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त वर्ष 2 का निगम का कोई पूर्ण-कालिक वेतन भीनी कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो 1 जिलम्बर, 1956 को निगम का कर्मचारी बना था और विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है;

(झ) "अवधेरणा" से सवारी भत्ता में कमी करना या अवधेरणा-सारणी में यथा उपर्युक्त वेतन-वृद्धि का न दिया जाना या वेतन हास अभिप्रेत है;

(झ) "आदेय प्रीमियम" से अभिप्रेत है, विकास अधिकारी संघठन के अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त कारबार के संबंध में निगम द्वारा प्राप्त प्रथम वर्ष के प्रीमियम का वह अनुपात जो समय-समय पर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय और सुरक्षत मूल्य निर्धारण वर्ष में समायोजित किया जाए।

(ट) नीचे दी गई तालिका के संभ (1) में विनिर्दिष्ट व्यापार धोन में कार्यरत विकास अधिकारी के संबंध में मूल्य निर्धारण वर्ष के बारे में "व्यय सीमा" से (जिसमें इसके पश्चात व्यय सीमा-सारणी कहा गया है) अभिप्रेत है, उस तालिका के संभ (2) की तस्थानी प्रविधि में यथा विनिर्दिष्ट उस वर्ष के आदेय प्रीमियम का प्रतिशत:

व्यय-सीमा सारणी

विविध विकास अधिकारी व्यापार धोन में कार्यरत है	आदेय प्रीमियम का प्रतिशत
(1)	(2)
क	22 प्रतिशत
ख	23 प्रतिशत
ग	24 प्रतिशत
घ	25 प्रतिशत
ज	26 प्रतिशत

टिप्पणी:— किसी भी मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी की व्यय-सीमा उस वर्ष के आदेय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। यदि किसी विकास अधिकारी का उस वर्ष का वार्षिक पारिश्रमिक व्यय-सीमा से ग्राधक है तो यह कहा जाता है कि उसने व्यय-सीमा पार कर ली है; ऐसे आधिकार्य या उस अनुपात को, जो उसके वार्षिक पारिश्रमिक का उस वर्ष के आदेय प्रीमियम से है, ऐसे आदेय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है।

(ठ) विकास अधिकारी के संबंध में "व्यापार धोन" से अभिप्रेत है, वह धोन जिसमें वह विकास अधिकारी को रूप में काम करने के लिए तैनात है और ऐसा विकास अधिकारी व्यापार धोन में कार्यरत तब कहा जाता है जब वह वह—

(क) किसी नगर, शहरी सीमा या कस्बे में काम कर रहा है, जिसमें अभिनिश्चित जन-संख्या 10 लाख से अधिक है;

- (क) किसी नगर, शहरी सीमा या कस्बे में काम कर रहा है, जिसकी अधिनियमित जनसंख्या 4 लाख या उससे अधिक, किन्तु 10 लाख से अधिक नहीं है,
- (ग) किसी नगर, शहरी सीमा या कस्बे में काम कर रहा है। (जो आमोंग लोक या अतिप्रामीण लोक नहीं है) जिसकी अधिनियमित जनसंख्या 4 लाख से कम है;
- (घ) किसी प्रामीण जल में काम कर रहा है, और
- (इ) यदि वह स्पष्टीकरण (4) में विनियिल्ट किसी अतिप्रामीण लोक या किसी पहाड़ी घोड़े में कार्य कर रहा है या किसी ऐसे अन्य पहाड़ी घोड़े में कार्य कर रहा है, जिसे केन्द्रीय सरकार, नियम के प्रारम्भ से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियमित विनियिल्ट करे।
- स्पष्टीकरण :**—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,—
- (1) “अधिनियमित जनसंख्या” से भारत सरकार की सबसे अधिम जनगणना रिपोर्ट के आधार पर अधिनियमित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है,
 - (2) विकास अधिकारी तथा “प्रामीण लोक” में कार्यरत कहा जाता है जब उसका मुख्यालय किसी ऐसे स्थान पर है, जिसकी अधिनियमित जनसंख्या 30,000 या उससे कम और उसके व्यापार लोक की अधिनियमित जनसंख्या 1,00,000 से अधिक नहीं है,
 - (3) विकास अधिकारी तथा “अतिप्रामीण लोक” में कार्यरत कहा जाता है जब उसका मुख्यालय किसी ऐसे स्थान पर है, जिसकी अधिनियमित जनसंख्या 10,000 या उससे कम और उसके व्यापार लोक की अधिनियमित जनसंख्या 60,000 से अधिक नहीं है;
 - (4) विकास अधिकारी “पहाड़ी लोक” में कार्यरत सब कहा जाता है जब उसका मुख्यालय भीन समुद्री स्तर से ऊपर 1000 मीटर ऊर उससे अधिक की ऊँचाई पर है, जिसकी अधिनियमित जनसंख्या 20,000 या उससे कम है और उसके व्यापार लोक की अधिनियमित जनसंख्या 75,000 से अधिक नहीं है।
 - (५) “दूरवागमी वर्ष” या “सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष” से, सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से ठोक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है,
 - (६) “विहित व्यय-सीमा” या “विहित सामग्री अनुपात” से नियम ५ के उपनियम (१) या उपनियम (२) के परन्तु के अनुसार अधिनियमित बढ़ाई गई व्यय-सीमा अभिप्रेत है जहाँ ऐसी व्यय-सीमा विकास अधिकारी पर लागू होती है, या जहाँ वह उस पर लागू नहीं होती है वहाँ पद से वह व्यय-सीमा अभिप्रेत होगी जो उसको लागू होती है:
- (ज) “सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख” से वह मूल्य निर्धारण तारीख अभिप्रेत है, जो उस तारीख से ठोक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी के कार्यपालन का, इस नियमों के अधीन किसी भी प्रयोग के लिए, मूल्यांकन किया जाता है या कर्मचारिवृन्द नियमों के अधीन इस पर किया गया था,
- (क) “सेवा” से वह अवधि अभिप्रेत है जो विकास अधिकारी के रूप में कर्तव्य पूरा करते हुए तथा कर्मचारिवृन्द नियमों के नियम ६९(४) के अधीन अमा की गई प्रासादारण छुट्टियों सहित, अन्य छुट्टियों पर बिताई गई है,
- (द) “उत्तरवर्ती वर्ष” से सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से प्रारम्भ होने वाली बाहर मास की अवधि अभिप्रेत है,
- (घ) “अवधिरेण सारणी” से नियम ७ के उपनियम (१) के भीत्री दी गई सारणी अभिप्रेत है,
- (न) “बढ़ाई गई व्यय सीमा सारणी” से नियम ५ के उपनियम (२) के भीत्री दी गई सारणी अभिप्रेत है,
- (प) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और जो कर्मचारिवृन्द नियमों में परिभाषित हैं, वही अन्य होंगे जो उनके कर्मचारिवृन्द नियमों में हैं।

पदावधि

इन नियमों के उपबोधी के अधीन रहते हुए, विकास अधिकारी, उसी अवधि तक और उसी रीति में पद धारण करेगा जिसमें कि नियम के अन्य कर्मचारी आवारण करते हैं।—

परन्तु वह अवधि का लागू व्यय सीमा का अनुपालन करेगा

परन्तु यह और कि किसी पुष्ट विकास अधिकारी की सेवाएं ऐसे गल कारबार उत्पादन के आधार पर जिससे उसको लागू व्यय सीमा से अधिक लागत अनुपात हुआ है, समाप्त नहीं की जाएगी जब तक कि नियम ७ में यथा उपविधित व्यय सीमा का अनुपालन करने का उसे अवसर प्रदान न किया गया हो।

४ विकास अधिकारीयों को लागू व्यय सीमा

(१) किसी विकास अधिकारी को लागू व्यय सीमा वह होगी जो व्यय सीमा की सारणी में विनियिल्ट है।

परन्तु जहाँ किसी विकास अधिकारी ने सुसंगत मूल्य निर्धारण १३ के प्रारम्भ के समय विकास अधिकारी के रूप में दस वर्ष से अधिक की सेवा की है, वहाँ सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए उसको लागू व्यय सीमा एक प्रतिशत तक बढ़ाई गई उसके व्यापार लोक को लागू व्यय सीमा ही यदि सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ के समय या उसके पूर्व, उसन ५० वर्ष की आयु पूरी कर ली है और यदि उसने ५२ वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो ऐसी व्यय सीमा में दो प्रतिशत तक और यदि उसने ५४ वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो ३ प्रतिशत तक १ अक्टूबर, १९८७ से बढ़ियी जाएगी।

(२) जहाँ भारतीय जीवन बीमा नियम विकास अधिकारी (सेवा के नियमों और शर्तों का उल्लंघन) नियम, १९८६ के नियम १० में अन्तर्विष्ट उपबोधी के अनुसरण में किसी विकास अधिकारी को दिया गया साम्यापूर्ण अनुतोष उसके वार्षिक पारिश्रमिक का भाग है, वहाँ भी दी जाएगी सारणी के सम्म (१) में विनियिल्ट मूल्य निर्धारण वर्षों के लिए उसकी लागू व्यय सीमा वह होगी जो सारणी के स्तर (२) में को तास्थानी प्रविधित में विनियिल्ट प्रतिशत तक १ अक्टूबर, १९८७ से बढ़ाई गई है:

बढ़ाई गई व्यय सीमा की सारणी

निम्नलिखित छाकों में बाहर मासों के किसी प्रथम दिन को प्रतिशत प्रारंभ होने वाले मूल्य निर्धारण वर्ष

(1)	(2)
-----	-----

(क) अक्टूबर, 1986—सितम्बर, 1987	2 प्रतिशत
(ख) अक्टूबर, 1987—सितम्बर, 1988	2 प्रतिशत
(ग) अक्टूबर, 1987—सितम्बर, 1989	1 प्रतिशत

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के परन्तुक में विनियिष्ट बढ़ाई गई व्यय सीमा व्यापार क्षेत्र 'क', 'ख', 'ग' और 'ध' की बाबत 1 अक्टूबर, 1987 को या उसके पश्चात पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को देय मूल्य निर्धारणों को लागू होगी :

परन्तु 1 अक्टूबर, 1987 को या उसके पश्चात किंतु अप्रैल, 1988 के पूर्व पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीखों को देय मूल्य निर्धारणों की बाबत व्यय सीमा का अनुपालन करने वा प्रवास यात्रा समय पर व्यय प्रवृत्त कर्मचारीबूद्धि नियमों की अनुसूची 3 में परा 5 के नीचे सारणी के अनुसार होगा ।

(4) उपनियम (1) और उपनियम (2) के परन्तुक में विनियिष्ट बढ़ाई गई व्यय सीमा व्यापार क्षेत्र "क" की बाबत 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को देय मूल्य निर्धारणों को लागू होगी ।

(5) उपनियम (1) या उपनियम (2) के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी अवधिरेणा सारणी के स्तंभ (2) में विनियिष्ट प्रतिशतता या नियम 7 के उपनियम (8) में विनियिष्ट प्रतिशतता में वृद्धि नहीं क, जाएगी ।

5. बेतन वृद्धियाँ

(1) किसी विकास अधिकारी द्वारा बेतन वृद्धियाँ साधारणतया कर्मचारीबूद्धि नियमों के विषय के अनुसार सामान्य क्रम में प्राप्त ही जाएंगी जब तक कि वह अधिकतम प्रेड में नहीं पहुंच गया हो या बतन वृद्धि नियम 7 या नियम 10 के अनुसार अनुज्ञात नहीं की जा सकती हो या कर्मचारीबूद्धि नियमों के नियम 39 के अधीन किसी अनुपालन व्यापार के रूप में नहीं रोकी जा सकती हो ।

(2) जहाँ किसी वर्ष में किसी विकास अधिकारी को कोई बेतन वृद्धि अवधिरेणा के रूप में नियम 7 के अनुसार नहीं दी जाती है, वहाँ ऐसी बेतन वृद्धि नियम में अस्तव्यष्ट उपबंधों के अनुगार के विषय किसी पश्चास्त्रवर्णी वर्ष में उसे नहीं दी जाएगी ।

6. सवारी भत्ता :

हर एक विकास अधिकारी ऐसे सवारी भत्ता का हकदार होगा जो समय समय पर नियम द्वारा दिया जाए ।

परन्तु किसी वर्ष में विकास अधिकारी को अनुमेय सवारी भत्ता नियम 7 के उपबंधों के अधीन होगा ।

7. व्यय सीमा के अनुपालन का अवसर:

(1) जहाँ पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में किसी विकास अधिकारी का वार्षिक पारिश्रमिक व्यय सीमा से अधिक है वहाँ उसकी मेवाएं मात्र उस आधार पर समाप्त नहीं की जाएगी यदि उसका मामला अवधिरेणा सारणी में व्यय उपचित सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से नियम 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अवधिरेणा बेकर नियमावधि जा सकते हैं जिससे कि उसे व्यय सीमा के अनुपालन करने का अवधार प्रवान किया जा सके ।

परन्तु अवधिरेणा सारणी के अनुगार अवधिरेणा देने के प्रयोजन के लिए उसके कार्यपालन का तर्क वार्षिक पारिश्रमिक और उसको लागू विविह व्यय सीमा के प्रति निर्देश से मूल्य निर्धारण किया जाएगा ।

अवधिरेणा—सारणी

क्रम सं.	जहाँ तदर्थे वार्षिक पारिश्रमिक विनियिष्ट व्यय सीमा से अधिक है या लागत अनुपालन विहित सीमा से अधिक है ।	अभियोग जहाँ सुसंगत मूल निर्धारण तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल निर्धारण वर्ष में तदर्थे वार्षिक पारिश्रमिक विनियिष्ट व्यय सीमा से अधिक है या लागत अनुपालन विहित सीमा से अधिक है ।
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 प्रतिशत से अधिक नहीं (परन्तु यह सब जबकि मूल निर्धारण वर्ष में सारांश अनुपालन 35 प्रतिशत से अधिक नहीं है)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2 प्रतिशत से अधिक किन्तु 8 प्रतिशत से अधिक नहीं (परन्तु यह सब जबकि मूल निर्धारण वर्ष में सारांश अनुपालन 35 प्रतिशत से अधिक नहीं है)	स.भ. में 30 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 50 प्रतिशत कटौती	म.भ. में 60 प्रतिशत कटौती	म.भ. में 60 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन वृद्धि नहीं	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन वृद्धि नहीं	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन वृद्धि नहीं
6 प्रतिशत से अधिक किन्तु 9 प्रतिशत से अधिक नहीं (परन्तु यह सब जबकि मूल निर्धारण वर्ष में सारांश अनुपालन 35 प्रतिशत से अधिक नहीं है)	स.भ. में 50 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन वृद्धि नहीं	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन वृद्धि नहीं	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन वृद्धि नहीं	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन वृद्धि नहीं

स.भ. में 50 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन वृद्धि नहीं	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन वृद्धि नहीं
---------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------

टिप्पण : इस सारणी के प्रयोजनों के लिए —

- (क) "स.ध. में कटीती" से सबारी भासा में कमी करना अभियंत्र है ;
 (ख) "कोई बेतन बुद्धि नहीं" से बेतन बुद्धि का न विद्या जाना अभियंत्र है ;
 (ग) "बेतन-डास" से एक प्रथम तक मूल बेतन में कमी करना अभियंत्र है ।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयाजनों के लिए—

(i) (क) ग्रामपोरा के अधिनियम्य के लिए मूल निर्धारण के प्रयोगोंना के लिए तर्बै वा विकापरिवर्तनिक प्रवर्तनिक रूप से अभिनियम्यत किया, जो प्रयोग से भी भौतिक विशेष वेतन, अविकलन वेतन, पृथक वेतन, घटागाई भत्ता और अन्य सभी भौतिकों का 12 गुणा समझ, जोएगा जिसके अन्तर्गत युवासंघ मूल्य निर्धारण तारीख के पूर्णवर्ती निर्धारण वर्षे के प्रथम दिन को किसी विकास अधिकारी को अनुबोध सकते हो और उसके लाभ निरोध आवाहीदारी या अनुप्रयुक्ति द्वारा जो मूल निर्धारण वर्ष के दौरान उसको व्यवहार है या मिला है और इसके अन्तर्गत ऐसे कुछ व्यथ भी हैं जो याता, आवाहीदारी टारीफों और श्रीम, प्रीमियम तथा भोटर यातों पर करों के बद्दल में उसे देय हैं या उसकी उसे प्रतिवृत्ति की गई है या वे उन पर उपगत हुए हैं :

परन्तु यदि उसके सवारी भस्त में उमके द्वारा, कोई यात्रा प्रजिन करते थे, विसी भिन्न प्रकार के यात्र को आप करने के परिणामस्वरूप प्रथमा यात्री भस्त के किसी गुनीरीक्षण के कारण पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई वृद्ध हुआ है तो उम थर्ड के दौरान उसका सदत बढ़ाया, यद्यपि सवारी भस्त उसको लाए तब्दि वर्षिक पारिश्रमिक निकालने के लिए जोड़ा जाएगा।

(क्ष) पूर्वगामी रीति में कदर्द वार्षिक पारिश्रमिक की संगणना की रीति अप्रेसेणा के प्रयोजन के लिए, 1 अप्रैल, 1988 बो या उसके पश्चात् एक वार्षीय मुर्मान मूल्य निर्धारण तरीख बो देय सभी मूल्य निर्धारणों को गणित करेंगी :

परन्तु मुमगत मूल निधारण तरीकों को जो 1 अप्रैल, 1989 को या उसके पश्चात् पड़ सकती है, देख मूल निधारणों के लिए यदि उपर्युक्त (क) में विभिन्न दर दी रखी में संभागित पूर्वज सी और जिसे इस उपर्युक्त में इसके पश्चात् त्रृ-‘मुमगत वर्ष’ कहा, यह है कि लिए तदर्थ वापिक परिश्रमिक मुमगत वर्ष के द्वारा पूर्वज सी मूल्य निधारण वर्ष के लिए उसी रीति में संभागित तदर्थ वापिक परिश्रमिक से 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो मुमगत वर्ष के लिए तदर्थ वापिक परिश्रमिक मुमगत वर्ष के द्वारा पूर्वज सी मूल्य निधारण वर्ष के लिए उपर्युक्त (क) के अनुसार संभागित तदर्थ वापिक परिश्रमिक का 110 प्रतिशत समझा जायगा :

परन्तु यह और कि यदि विकाम अधिकारी सवारी भत्ते में उसके द्वारा कोई यात्रा अनुमति करने या इसी भिन्न प्रकार के यात्रा को क्य करने के परिणामस्वरूप अथवा सवारी भत्ते के इसी पुनरीकाण के बारण पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई वृद्धि हुई है तो उस वर्ष के दौरान उसको संवत्त बढ़ाया गया भवारा मता उनको लागू सर्व वापिक पारिश्रमिक निकालने के लिए जीड़ा जाएगा।

(ग) उपर्युक्त (क) या उपर्युक्त (ख) में विभिन्न बातों के हास्ते हुए भी जहाँ किसी विकास अधिकारी ने विकास अधिकारी के रूप में 10 वर्ष से अधिक को सेवा की है और मुसंगत मूल निवारण वर्ष के प्रारम्भ के समय 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वहाँ उसके कार्यपालन का 'उस मूल्य निवारण वर्ष' के लिए जिस के प्रारम्भ के समय उसने इस अंडे में विनियिष्ट प्रवेशाद्य पूरी कर ली है, अधिप्रेरणा के अधिनिर्णय के प्रयोजन के लिए उसको लाए गारिक पारित्यक के प्रतिनिर्देश से प्रारम्भिक रूप से अविनियिष्ट रूप में मूल्यांकित किया जाएगा और ऐसा वाचिक पारित्यक अभिक उसके समाने में तदूर्ध वाचिक पारित्यक भी समझा जाएगा:

परम्परा ऐसे किसी विकास प्रथाओं की व्यापत जिसने 1 अप्रैल, 1938 से पूर्व किसी भारोद्ध को या किसी मूल निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ के समय या उसके पूर्व पूर्वित सेवा और आमु के बारे मन्त्रीकाओं को पूर्ति का है, तथा वार्षिक परिवर्त्मिक 1 अक्टूबर, 1986 को या उसके प्रत्यात् प्रारम्भ होने वाले मुश्यमत मूल निर्धारण वर्ष में प्रथमिक रूप से अधिनियमित उसको लागू वार्षिक परिवर्त्मिक इस रूप में माना जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि विकास अधिकारी सवारी भत्ते में उसके द्वारा कोई यान अभिन्न करने या विस्तीर्ण प्रकार के यान को क्षय करने के परिणामस्थल अथवा सवारी भत्ते के किसी तुनरीकाण के कारण पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई बुद्धि नहीं है तो उसका संदर्भ बड़ाया गया गवारी भत्ता में पृष्ठासवर्ती वर्ष में और उसके पश्चात् उसका तथ्यवाचिक पारिथमिक लिङ्गालने के लिए जोड़ा जाएगा ।

(ब) पूर्वगामी उपचरणों में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी मूल निर्धारण वर्षे में किसी विकास अधिकारी का वाचिक पारिश्रमिक पूर्वकृष्ण विनियोग रीति में संगति तथा वाचिक पारिश्रमिक से कम था

तो ऐसा वार्षिक पारिश्रमिक अवधेरणा के अधिनियम के लिए मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उस मूल्य निर्धारण वर्ष में उसको लागू तदर्थं वार्षिक पारिश्रमिक समाप्त जाएगा।

(इ) जहाँ विकास अधिकारी को सेवाओं के निवारणों और शतों के साधारण पुनरीकाप से संबंधित किसी नियमों के अनुसरण में बेतनमान या भतों में कोई परिवर्तन किया जाता है वहाँ पूर्णगामी उपबंधों के अधीन तदर्थं वार्षिक पारिश्रमिक की संगणना अधिनियम की घारा 48 के अधीन जारी किए गए ऐसे नियमों के उपबंधों के अधीन होगी।

(ए) इस खण्ड के आधार पर तदर्थं वार्षिक पारिश्रमिक की संगणना केवल अवधेरणा के प्रयोजन के लिए होनी और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए वार्षिक पारिश्रमिक को हिसाब में लिया जाएगा।

(छ) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (i) के प्रयोजनों के लिए पारिश्रमिक का जिसके लिए कर्मचारी इन नियमों के अधीन सामान्य अनुक्रम में पाल है, परिकलन या उसको संगणना द्वारा पारिश्रमिक प्रशिक्षित रूप से अधिनियमित किया जाएगा और उसके लिए विशेष परिस्थितियों के अधीन, जैसे निवारण, असाधारण छुट्टी या अधीन बेतन पर बीमारी छुट्टी या किसी अन्य कारणण पारिश्रमिक की किसी छट्टी, कभी या उसके किसी आग को रोकने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) अवधेरणा सारणी का लागू किया जाना नियम 9 में अन्तिम उपबंधों के अधीन होगा, परन्तु यह तब जबकि विकास अधिकारी को सेवाओं को इस नियम के उप नियम (2) या उप नियम (8) के अधीन समाप्त नहीं किया जा सकता।

(iii) अवधेरणा सारणी के प्रयोजन के लिए, किसी विकास अधिकारी को तदर्थं वार्षिक पारिश्रमिक क्रमिक अवसर पर विहित अन्य सीमा से अधिक तब मता जाएगा जब ऐसा पारिश्रमिक दो समावार मूल्य निर्धारण वर्षों में ऐसी अन्य सीमा से अधिक रहता है, जले ही अन्य सीमा से प्राप्तिक का प्रतिशत निम्न हो और किसी मूल्य निर्धारण वर्ष को भी किसी विकास अधिकारी अन्य सीमा पार करता है, भले ही वहाँ कोई अवधारणा न हो, यह अधिनियमित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा कि क्या क्रमिक अवसरों पर अन्य सीमा पार हुई है और क्रमिक अवसरों पर अवधेरणा सुसंगत मूल निर्धारण तारीख के ठोक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में विद्युत अन्य सीमा के आधिक्य के अनुरूप होगी।

(iv) अवधेरणा सारणी को निरंतर लागू किया जाएगा, यदि विहित अन्य सीमा का अनुपालन करने के पश्चात् विकास अधिकारी किसी प्रकार तारीख को पुनः ऐसे पार कर जाता है।

(2) यदि उपनियम (1) में अन्तिम उपबंधों के लागू किए जाने के फलस्वरूप निकाला गया मूल बेतन विकास अधिकारी के बारे में लागू घेउ के न्यूनतम से भी कम पड़ता है तो उसका मूल बेतन ऐसे न्यूनतम पर ही नियत कर दिया जाएगा।

परन्तु इस उपनियम के अधीन अनुपालन पर मूल बेतन का नियम किया जाना विकास अधिकारी की सम्पूर्ण सेवा के बोगान एक से अधिक बार अनुपालन नहीं किया जाएगा और यदि किसी दूसरे अवसर पर इस प्रकार निकाला गया मूल बेतन ऐसे न्यूनतम से कम पड़ता है तो उसका सेवाएं नियम 8 के अनुसार समाप्त की जा सकती।

(3) (क) जहाँ किसी विकास अधिकारी के मूल बेतन में उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कभी की जाती है या यह नियत किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पुनरोक्ति मूल बेतन" कहा गया है) वहाँ उसे केवल ऐसे भतों और अन्य फायदे अनुपालन होंगे जो उस मूल बेतन पर उसे अनुरूप हैं;

(ख) जहाँ उसके सवारी भतों में कभी की गई है, वहाँ यह बेतन ऐसे सवारी भतों का हकदार होगा जो पुनरोक्ति मूल बेतन के आधार पर इस प्रकार कम किया गया है।

परन्तु वार्षिक पारिश्रमिक का सठन तो बेयरिक इस देवर और विषारण से दिया जाएगा और अन्य सीमा का अनुपालन उसके द्वारा पालन करने के पारिणामस्वरूप पिछली अवधि के लिए बेतन का कोई बता सम्बाय नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1), (2), (3) के उपबंधों को कार्यवित करने के लिए सकाम प्राधिकारी होता और वह सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उस उपनियमों में विनियिष्ट विधयों को अधिकारित करेगा :

परन्तु सम्बद्ध सकाम प्राधिकारी इस नियम के अधीन किसी विधय का विनियिष्ट करने के पूर्व विकास अधिकारी को अस्यावेदन करने का प्रवसर प्रदान करेगा।

(5) जहाँ उपनियम (4) के परन्तुके मध्योन अभिप्राप्त अन्यावेदन से—

(क) आवेद्य प्रामियम या अन्य आकड़ों की संगणना में किसी वास्तविक असूलियों का पता चलता है, तो सकाम प्राधिकारी पुनरोक्ति आकड़ों के अनुपालन प्रत्येक सीमा तक भतने विनियिष्ट को पुनरोक्ति करेगा और अस्यावेदन का निपटाने के लिए समूचित आदेश पारित करेगा;

(ख) यदि अन्य सीमा में डोन को उचित ठहराने के लिए अन्यावेदन से किसी ऐसे कारण का पता चलता है, जो विकास अधिकारी के नियवण के पर भा और दुर्घटना या बीमारी, और यदि वह तक देता है उस आधार पर अवधेरणा का अधिनियम प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए तो सकाम प्राधिकारी उस अन्यावेदन को विनियिष्ट के लिए जोन प्रबंधक को भेजेगा।

(6) यदि जोन प्रबंधक का समाधान हो जाता है कि अन्यावेदन में कोई गुणाग्रण है तो वह मामले को परिस्थितियों पर विकार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह टीक समझे।

(7) ऐसा विकास अधिकारी जिसका अस्यावेदन जोन प्रबंधक द्वारा नापूर्ण कर दिया गया है, उस मामले को बाबत अध्यक्ष को एक आपन प्रस्तुत करेगा।

(8) इस नियम के पूर्णगामी उपबंधों में किसी शात के होते हुए भी जहाँ किसी पूर्ववर्ती वर्ष में (जिसे इस उपनियम में इसके पश्चात् "मूल वर्ष" कहा गया है) किसी विकास प्राधिकारी का तदर्थं वार्षिक पारिश्रमिक उस वर्ष के आवेद्य प्रामियम के 50 प्रतिशत से अधिक और सुसंगत वर्ष और मूल वर्ष को ठोक पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्षों में तदर्थं पारिश्रमिक का कूल योग उन तीन वर्षों में आवेद्य प्रामियम के कूल 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो उसकी सेवाएं नियम 8 के अनुसार समाप्त की जा सकती।

6.—कुछ मामलों में सेवा की समाप्ति :

(1) जहाँ कोई विकास अधिकारी अन्य सीमा का अनुपालन करने में असफल रहा है और जहाँ ऐसी सीमा का अनुपालन करने का नियम 7 के उपबंधों के अधीन कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सका था वहाँ जोन प्रबंधक तीन मास की बूकना या उसके बदले में बेतन देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है:

परन्तु विकास अधिकारी को उसकी प्रस्तावित सेवा-समाप्ति के विळु भारण बताने का प्रवसर दिया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील, प्रबंध निवेदक को को जाएगी और कर्मचारित्वन्द नियमों के नियम 41, 42, 43, 44 और 45 के उपबंध, जहाँ तक हो सके, वहाँ तक ऐसी अपील को लागू होगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन अपील को जाने पर, प्रबंध निवेदक भारण के अधिनेत्र पर विकार करके और मामले की परिस्थितियों को व्याप में रखकर गुणाग्रण के आधार पर आवेद्य पारित कर सकता।

9. अवधिकारी का आवश्यकन :

(1) “कोई वेतन बृद्धि नहीं” से निम्न अवधिकारी सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख (जिसे इसमें इसके पश्चात् “सुसंगत देय तारीख” कहा गया है) से प्रधिनिर्णीत नहीं की जाएगी किन्तु अनुबर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तक प्राप्तिविभिन्न रखी जाएगी, यदि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई विकास अधिकारी, जिसने कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, ऐसी विहित व्यय सीमा पार कर चुका है, जिससे अवधिकारी के अनुसार अवधिकारी विद्या जाना आवश्यक हो जाता है :

परन्तु यह तब जब कि ऐसे सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष से अनुपालन निररंतर अवधिकारी तक विहित व्यय सीमा पार नहीं की है या, जहाँ उसने पांच वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है किन्तु कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है और उसने विकास अधिकारी के रूप में पद का कार्य सार अनुपालन की तारीख से किसी वर्ष में विहित व्यय सीमा पर नहीं की है।

(2) जहाँ विकास अधिकारी उस नियम (1) में निर्विष्ट अनुबर्ती वर्ष में विहित सीमा का अनुपालन करता है वहाँ ऐसी अवधिकारीओं को जो प्राप्तिविभिन्न रखी गई है, प्रधिनिर्णीत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और यदि कोई वेतन बृद्धि जो सुसंगत विधायिक तारीख को उसे अनुपालन प्रोत्तम हो गई होती, अवधिकारी के रूप में अनुपालन की गई थी तो ऐसी वेतन बृद्धि सुसंगत देय तारीख से निर्भीचित कर दी जाएगी।

(3) जहाँ विकास अधिकारी किसी ऐसे अनुबर्ती वर्ष में विहित व्यय सीमा को पार कर चुका है वहाँ ऐसी अवधिकारी जो प्राप्तिविभिन्न वर्ष में उसको संवाल अधिकाय पारिश्रमिक की समुचित वसूली आगामी वर्ष के उसके वेतन में से की जाएगी और “कोई वेतन बृद्धि नहीं” की अवधिकारी यदि कोई हो, अंतिम हो जाएगी और वह ऐसे अनुबर्ती वर्ष में विहित व्यय सीमा का अनुपालन करने में अपनी असफलता के लिए अवधिकारी सारणी के अनुसार कार्रवाई किए जाने का भी दायरी हो जाएगा।

(4) जहाँ अवधिकारीओं को उपनियम (2) के अनुसार प्रवर्तित नहीं किया जाता है या वेतन बृद्धि सुसंगत देय तारीख से निर्भीचित की जाती है वहाँ उपनियम (1) के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष को, व्याप्तिविभिन्न वर्ष या तीन वर्ष की निररंतर सेवा की संगतता के प्रयोजन के लिए उस वर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसमें उसने विहित व्यय सीमा पार नहीं की है।

(5) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई विकास अधिकारी ऐसे प्रक्रम पर है जहाँ वकाता रोध हो वहाँ उस वकाता रोध से परे उसे कोई वेतनबृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि उसमें नियम 10 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है।

10. वकाता रोध :

(1) जहाँ किसी वेतनमान में वकाता रोध है वहाँ विकास अधिकारी 1 अप्रैल 1988 को या उसके पश्चात तब तक रोध के आगे वेतन बृद्धि पाने के योग्य प्रमाणित मही किया जाएगा जब तक कि —

(a) सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख (जिसे इस उपनियम में इसके पश्चात् “सुसंगत वर्ष” कहा गया है) के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में उसके वार्षिक पारिश्रमिक के प्रति निवेश से उसका लागत अनुपालन 20 प्रतिशत से अधिक नहीं था, और

(b) उसने सुसंगत वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वो मूल्य निर्धारण वर्ष में उसको सार्व व्यय सीमा पार नहीं की है।

(2) जहाँ किसी विकास अधिकारी को ऐसा वकाता रोध पार करने की जिसे पार करने से उसे पहले रोक दिया गया था, अनुपालन दी जाती है तो उसे भत्ताली तारीख से केवल एक वेतन बृद्धि का अनुपालन दी जाएगी :

परन्तु वेतन बृद्धि के हुआ दिए जाने पर एक से प्रधिक वेतन बृद्धि केवल तब अनुपालन की जा सकती जब वह नियम 11, 12, 13 या 14 के अनुसार किसी वेतन बृद्धि के लिए पात्र हो जाता है।

(3) जहाँ किसी विकास अधिकारी ने वकाता रोध पार कर नियम 1 किन्तु उसे किसी कारणबाट बाहे जो भी हो वकाता रोध से ने थे वह दिया गया है वहाँ उसे वकाता रोध को पार करने के अनुपालन केवल सब दो जा सकती जब वह अपनी अपाली वेतन बृद्धि के लिए पात्र हो जाता है जब तक कि उसे वेतन बृद्धि कार्रवायित नियमों के नियम 39 के अर्थात् किसी अनुपालनमानक अव्यवधारण के रूप में रोकी नहीं गई है।

11. 31-3-88 को या उसके पूर्व पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख के पूर्व कार्रवायित नियमकी अनुसूची 3 के अनुसार मूल वेतन में कटौती का भूलभावी प्रस्तावन

(1) जहाँ किसी विकास अधिकारी ने इस नियम में विनियोग रीति में 1 अप्रैल 1988 के पूर्व पड़ने वाली मूल्य निर्धारण तारीख के लिए सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्षों में व्यय सीमा का अनुपालन करना जारी रखता है और वह तत्पश्चात व्यय सीमा का अनुपालन करना जारी रखता है वहाँ 20 जून, 1979 के पश्चात उसके मूल वेतन में इस आधार पर की गई कटौती कि उसने किसी ऐसे मूल्य निर्धारण वर्ष में जिसकी वापत सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख 31 मार्च, 1988 को या उसके पूर्व पढ़ रही थी, व्यय सीमा पार कर चुका है (मूल वेतन में ऐसी कटौती को इसमें उसके पश्चात “पिछले वेतनहास” कहा गया है) उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार प्रत्यावर्तित की जा सकती:

परन्तु यह तब जब कि जहाँ कोई विकास अधिकारी पिछली वेतनहास के प्रत्यावर्तित के लिए आहट हो जाता है वहाँ पिछला वेतनहास थो 20 जून, 1979 के पश्चात वाली मूल्य निर्धारण तारीख को पड़ने वाले मूल्य निर्धारण के फलस्वरूप पहली बार किया गया था, प्रथमतः प्रत्यावर्तित किया जाएगा, पिछला वेतनहास जो तत्पश्चात किया गया था प्रगती बार प्रत्यावर्तित किया जाएगा और आगे भी इस प्रकार किया जाता रहेगा।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए किसी वर्ष से संबंधित पिछला वेतनहास में वेतनमान में का एक से प्रधिक प्रक्रम सम्मिलित होगे।

(2) इस नियम का फायदा विकास अधिकारी को केवल तब प्रोत्तम होगा जब उसने 1 अप्रैल 1987 को या उसके पश्चात पड़ने वाली मूल्य निर्धारण तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में किन्तु 1 अप्रैल 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात “केन्द्रीय वर्ष” कहा गया है) और केन्द्रीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वो निर्धारण वर्षों में व्यय सीमा का अनुपालन किया है और वह इस नियम के फायदे के लिए तब तक पात्र बना रहेगा जब तक वह केन्द्रीय वर्ष के ठीक आगामी अनुबर्ती मूल्य निर्धारण वर्षों में व्यय सीमा का अनुपालन करता है और यदि किसी मूल्य निर्धारण वर्ष में द्वारा जिसमें वह व्यय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, यह अबला विचित्र हो जाती है तो वह ऐसे मूल्य निर्धारण वर्ष से सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को या उसके पश्चात इस नियम के अधीन फायदा प्राप्त करना बंद कर देगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, “शुरूला” से ऐसी तीन या प्रधिक प्रविच्छिन्न मूल्य निर्धारण वर्षों की शुरूला अभिवृत है जिसमें विकास अधिकारी ने व्यय सीमा पार नहीं की है:

परन्तु केन्द्रीय वर्ष की ठीक आगामी मूल्य निर्धारण वर्ष या उसके पश्चात किसी मूल्य निर्धारण वर्ष की संगतता उन्हें अनुबर्ती मूल्य निर्धारण वर्षों के प्रयोजनों के लिए केवल तब की जा सकती जब वह ऐसे अनुबर्ती वर्ष में विकास अधिकारी का सागत अनुपालन व्यय सीमा के दो प्रतिशत से प्रधिक नहीं है।

(3) उपनियम (4) और उपनियम (5) के उपर्योगों के अधीन रहते हुएः—

(i) जहाँ कोई विकास अधिकारी केंद्रीय वर्ष में 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात पड़ने वाली पूर्ण मूल्य निर्धारण तारीख को व्यय सीमा का अनुपालन करता है और उसे तीन वर्षों की किसी समिक्षित शृंखला का श्रेय प्राप्त है वहाँ एक वर्ष से संबंधित पिछले बेतनहास प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष की तारीख से प्रत्यावर्तित किए जा सकते।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विकास अधिकारी के संबंध में तीन वर्ष की समिक्षित शृंखला” से उस केंद्रीय वर्ष और वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती भी मूल्य निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें उस ने व्यय सीमा का अनुपालन किया है,

(ii) यदि, तीन वर्ष की किसी समिक्षित शृंखला के अतिरिक्त किसी विकास अधिकारी का तीन वर्ष की गत शृंखला का एक ऐसी गत शृंखला से प्रधिक का श्रेय प्राप्त है तो उतनी वर्षों से जितनी तीन वर्ष की निरन्तर शृंखलाएँ हैं संबंधित पिछले बेतन हास वांड (i) में निर्दिष्ट प्रथम मूल्य निर्धारण तारीख से प्रत्यावर्तित किए जा सकते।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विकास अधिकारी के संबंध में ‘तीन वर्ष की गत शृंखला से केंद्रीय वर्ष की ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष और ऐसे शृंखलाओं वाले मूल्य निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती मूल्य अधिकारी का श्रेय प्राप्त है जिसमें किसी विकास अधिकारी ने व्यय सीमा का अनुपालन किया है।

(iii) यदि विकास अधिकारी को तीन वर्ष की समिक्षित शृंखला प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है किन्तु तीन वर्ष की गत शृंखला या ऐसी गत शृंखलाओं की अपेक्षित संख्या के आवाह से पिछले बेतनहास प्रत्यावर्तित नहीं किए जा सकते, और यदि केंद्रीय वर्ष के ठीक आगामी मूल्य निर्धारण वर्ष से संबंधित सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को उसके नामे में किंवदं शृंखला प्रोवैश्वान आती है तो आदेश पिछले बेतनहास यदि कोई हूँ, ऐसी सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से इस वर्ष के अधीन रहते हुए प्रत्यावर्तित किए जा सकते। कि जहाँ एक वर्ष से संबंधित मूल बेतन में कभी के अंतर्गत बेतनमान में एक से प्रधिक प्रक्रम समिक्षित है वहाँ आदेश पिछले बेतनहास का कोई प्रत्यावर्तन तब तक देय नहीं होगा जब तक कि आगे लागत से बेतनमान में कम से कम एक प्रक्रम को समर्पण प्राप्त नहीं होता किन्तु विकास अधिकारी उस वर्ष से संबंधित मूल बेतन में कभी के शेष प्रक्रम के प्रत्यावर्तन के लिए भागे भवसर पर अर्थित हो सके और ऐसे भवसर पर ऐसे शेष प्रक्रमों का एक वर्ष से संबंधित मूल बेतन में कभी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी विकास अधिकारी के संबंध में “अद्वाला बेतन” से केंद्रीय वर्ष और उस केंद्रीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती और अनुवर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष जिसमें विकास अधिकारी ने व्यय सीमा का अनुपालन किया है;

(ख) “आदेश पिछले बेतनहास” से एक वर्ष में एक या प्रधिक प्रक्रमों तक मूल बेतन में की गई कभी अभिप्रेत है जो या जिसका भाग यदि प्रत्यावर्तित किया गया तो उससे आवाहागत अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहेगी;

(ग) “आवाहागत” से वह अनुपालन अभिप्रेत है जो सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख (जिसके अंतर्गत उस तारीख को और उससे सभी बेतन शुद्धिया और प्रस्तावित प्रत्यावर्तन भी है) को किसी विकास अधिकारी को आगे वार्षिक पारिश्रमिक का पूर्ववर्ती वर्ष की आवेद्य प्रभियम से है और आवाहागत अधिकतम सीमा के अन्तर्गत तब समझी जाएगी जब किसी विकास अधिकारी को आगे ऐसा वार्षिक पारिश्रमिक ऐसे आदेश प्रभियम की उसकी अधीन सीमा के प्रतिशत से अधिक नहीं है,

(ब) “प्रत्यावर्तन” से पहले बेतनहास का प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है (जाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

(iv) यदि यदि (i) से खंड (iii) के उपर्योगों का अनुपालन करने के पश्चात वेतनहास प्रत्यावर्तित किए जाने लें हैं दो तीन वर्ष की सुसंगत शृंखला के सिल अतिरिक्त आदेश पिछले बेतनहास प्रत्येक ऐसी संबंधित मूल्य निर्धारण तारीख से जितने वाले भवने नाम से अप्रगति शृंखला शृंखला अधित करता है, प्रत्यावर्तित किए जा सकते।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) कलेंडर वर्ष से प्रारंभ होने वाली किसी प्रवैश्वान के संबंध में “अनुपालन शृंखला” सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से उस केंद्रीय वर्ष के प्रारंभ तक जिसमें विकास अधिकारी ने व्यय सीमा का आलन किया है, पीछे संगठित तीन वर्ष की शृंखला अभिप्रेत है,

(ख) ‘तीन वर्ष की सुसंगत शृंखला’, मे सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख के टीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की शृंखला अभिप्रेत है केवल जिसका उस तारीख को आदेश पिछले बेतनहास के प्रत्यावर्तन के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा।

(4) यदि विकास प्रधिकारी बेतनमान में ऐसे प्रक्रम पर है, जहाँ कोई दमाता-रोध ही वहाँ कोई प्रत्यावर्तन तब तक अनुपालन नहीं होगा जब तक कि वह उस मूल्य निर्धारण तारीख के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में जिसको वह अवधार प्रत्यावर्तन के लिए अद्वित हो सके, नियम 10 के अनुसार दमाता-रोध पर करने के लिए पात्र नहीं हो जाता है।

(5) कोई प्रत्यावर्तन अनुपालन नहीं होगा यदि, प्रत्यावर्तन पर, विकास प्रधिकारी बेतनमान में किसी ऐसे प्रक्रम पर पहुँच जाएगा जिस पर वह इस आधार पर नहीं पहुँच पाता कि उसने व्यय सीमा पार की थी और ऐसी दशा में प्रत्यावर्तन बेतनमान में उस प्रक्रम तक सीमित होगा जिस पर वह सामान्य रूप से पहुँच पाता।

12. 31-3-1988 को या उसके पूर्व पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख के पूर्व कर्मचारिकृत नियमों की अनुसूची 3 के अनुसरण में मूल बेतन में की गई कभी का आवी प्रत्यावर्तन—अनुकृति रीति:

(1) नियम 11 के उपनियम (4) और उपनियम (5) के अधीन रहते हुए, यदि किसी विकास अधिकारी का लागत अनुपालन 1 अप्रैल, 1989 को या उसके पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1992 के पूर्व पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीखों के पूर्ववर्ती प्रथम, द्वितीय या तृतीय मूल्य निर्धारण वर्ष में 15% से अधिक नहीं है तो 31 मार्च, 1988 को या उसके पूर्व पड़ने वाली मूल्य निर्धारण तारीखों के संबंध में एक या प्रधिक वर्षों से संबंधित पिछले बेतनहास नियम 11 के उपनियम (1) के पश्चात् में विनिर्दिष्ट रीति में, सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीखों से, उस विस्तार तक भावी लागत अधिकतम सीमा तक रहती है, प्रत्यावर्तित किए जा सकें।

परन्तु यदि विकास प्रधिकारी नियम 11 के अनुसार किसी प्रत्यावर्तन के लिए भी पात्र है तो वह उस नियम या इस नियम के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए आपत्ति विद्यम होता।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “पिछले बेतनहास,” “प्रत्यावर्तन” और “भावी लागत” पदों के लिए वर्थ होते जो उनके नियम 11 में हैं।

13. जहाँ सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख 1-4-1988 को या उसके पश्चात् पड़ती है, वहाँ मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप अवधेणा—सारणी के अनुसार मूल बेतन में की गई कभी का पुनः स्थापन

(1) 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप किसी विकास अधिकारी के मूल बेतन में की गई कभी की प्रभियम ऐसे इसमें इसके पश्चात् “भावी बेतनहास” कहा गया है।

को इस नियम या नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पुनः स्थापित किया जा सकेगा।

(2) जहाँ कोई विकास अधिकारी इस नियमों के अनुसार पुनः स्थापन के लिए अर्हित करता है वहाँ मूल बेतन में कमी जो पहली बार 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात की गई थी, प्रथमतः पुनः स्थापित की जाएगी; मूल बेतन में कमी जो तत्पचात् की गई थी, अगली बार पुनः स्थापित की जाएगी और इस प्रकार की जाती रहेगी।

परन्तु यदि कोई विकास अधिकारी उस मूल निर्धारण तारीख के जिससे उसके मूल बेतन में कमी जो गई थी, आगामी पाँच मूल निर्धारण वर्षों के भीतर पुनः स्थापन के लिए अर्हित होने में असफल रहता है तो उस कमी का कोई पुनः स्थापन नहीं किया जाएगा और उस दशा में कुल मूल बेतन में अगली कमी, यदि कोई हो, पुनः स्थापन के लिए वेय मानी जाएगी यदि वह बाद में पुनः स्थापन के लिए अर्हित हो जाता है।

परन्तु यह और कि इस नियम और नियम 14 के अधीन मूल बेतन में कमी का पुनः स्थापन विकास अधिकारी के रूप में पूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल तीन व्यवर्तनों तक सीमित रहेगा।

(3) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि 1 अप्रैल 1988 को या उसके पश्चात् पहले बाली किसी मुसंगत मूल निर्धारण तारीख को मूल निर्धारण तारीख से यह प्रकट होता है कि किसी विकास अधिकारी ने पूर्ववर्ती वर्ष में व्यय सीमा पार नहीं की है और यह कि ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष और अगले दो पूर्ववर्ती वर्षों में लागत अनुपात कुल मिलाकर उन सीन वर्षों के लिए (जिन्हें इसमें पश्चात् तीन वर्षों का ज्ञाक कहा गया है) सम्मिलित व्यय सीमा से अधिक नहीं है तो आदेय चालू बेतनहास मुसंगत मूल निर्धारण तारीख से पुनः स्थापित किया जाएगा,

परन्तु किसी पूर्ववर्ती वर्ष में विकास अधिकारी व्यय सीमा का अनुपालन नहीं करता है तो वह पुनः स्थापन के लिए तब अर्हित हो सकेगा जब किसी पश्चात्वर्ती मुसंगत मूल निर्धारण तारीख को तीन वर्षों का ज्ञाक हो।

परन्तु यह और कि एक वर्ष से अनधिक से मंबंधित चालू बेतनहास का एक मुसंगत मूल निर्धारण तारीख को पुनः स्थापन नियम जाएगा थोड़े ही भावी लागत एक वर्ष से अधिक बेतनहास के पुनः स्थापन का समर्थन करे।

स्थाटीकरण ——उम नियम के प्रयोगनों के लिए—

- (1) “तीन वर्ष का ज्ञाक” से अभिवृत है ऐसा प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें विकास अधिकारी ने व्यय सीमा पार नहीं की है और अगले दो पूर्ववर्ती वर्षों ;
- (2) “आदेय चालू बेतनहास” में एक वर्ष में मंबंधित चालू बेतनहास अभिवृत है जो यदि पुनः स्थापित किया गया, तो किसी भी भावी लागत को अधिकतम सीमा के अन्तर्गत रखेगा;
- (3) “भावी लागत” से वह अनुपात प्रतिवृत है जो मुसंगत मूल निर्धारण तारीख (जिसके अन्तर्गत उम तारीख को और से अभी बेतन वृद्धियाँ और प्रस्तावित पुनः स्थापन भी हैं) को किसी विकास अधिकारी द्वारा लागू वार्षिक पार्श्वाधिक धरा पूर्ववर्ती वर्ष की अंतिम प्रतिवृत में है और भावी लागत को अधिवृतम सीमा के अन्तर्गत नममा जाएगा यदि किसी विकास अधिकारी को लागू ऐसा पार्श्वाधिक ऐसे अदेय प्रतिवृत में उपके व्यय सीमा के प्रतिशत में अधिक नहीं है।

(4) नियम 11 के उपनियम (4) और उपनियम (5) के उपबंध, जहाँ तक दूसरे बेतन में कमी के पुनः स्थापन को बैठे ही लागू होते हैं ऐसे कि वे ऐसी कमी के प्रत्यावर्तन को लागू होते हैं।

14. जहाँ सुसंगत मूल निर्धारण तारीख 1-4-1988 को या उसके पश्चात् पड़ती है वहाँ मूल निर्धारण के परिणामस्वरूप अन्वेषणान्वारणी के अनुसार मूल बेतन में की गई कमी का पुनः स्थापन—अनुकूली रीति:—

नियम 13 के उपनियम (2) और उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई विकास अधिकारी तीन क्रमागती मूल निर्धारण वर्षों में व्यय सीमा पार नहीं करता है तो एक वर्ष से संबंधित चालू बेतन हास ऐसे पिछले मूल निर्धारण वर्ष की ठीक आगामी सुसंगत मूल निर्धारण तारीख से पुनः स्थापित किया जा सकेगा।

15. भविष्य निधि

(1) भारतीय जीवन बोमा नियम विकास अधिकारी (सेवा के निवारणों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम 1986 के नियम 8 में किसी बात के होने हुए थी, जहाँ नियम 11, 12, 13 या 14 में अंतिवृत्त उपबंधों के अनुसार सुसंगत मूल निर्धारण तारीख से किसी विकास अधिकारी को पिछले बेतनहास या चालू बेतनहास प्रत्यावर्तित या पुनः स्थापित किया जाते हैं। यहाँ नियम आपने द्वारा स्थापित भविष्य निधि में (जिसे इसमें पश्चात् “निधि” कहा गया है) में उस प्रबंधि के संबंध में जिसके लिए ऐसे बेतनहास प्रत्यावर्तित या पुनः स्थापित किए गए हैं, ऐसे बेतनहासों में समाविष्ट मूल बेतन के कुल योग का 8½ प्रतिशत की अधिकतम रकम का अभिदाय करेगा :

परन्तु यदि उस प्रबंधि के दोरान या उस प्रबंधि के किसी भाग के दोरान जिसमें उक्त बेतनहास पश्चृत ये वह दर जिस पर नियोजक का अभिदाय 8½ प्रतिशत में अधिक था तो नियम सुसंगत प्रबंधि से संबंधित मूल बेतन के उम भाग में ऐसी अधिक दर पर अभिदाय कर सकेगा :

परन्तु यह और कि विकास अधिकारी निधि में नियम से अपेक्षित अभिदायों के बगबर रकम का निधि के नियमों के अनुसार और उस रीति में जिसका उसे नियम द्वारा निरेश दिया गया है, अपने अतिरिक्त अभिदाय काव्य के हृप में अभिदाय करेगा ।

(2) नियम निधि में तब और उम विस्तार तक जिस तक विकास अधिकारी उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन ऐसे अतिरिक्त अभिदाय करता है, अभिदाय करेगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन नियम द्वारा किए गए अभिदाय किसी ऐसे प्रयोगन के निए उपलब्ध नहीं होने गे जिसके लिए नियोजक के प्रभिदाय निधि के नियमों के अधीन उपनियम तभी हैं ।

(4) इस नियम की कोई बात ऐसे किसी विकास अधिकारी को लागू नहीं होगी जो नियम द्वारा अनुमोदित किसी प्रधिवार्षिकी निधि में अभिदाय कर रहा है ।

16. विशेष मामले :

(1) प्रबंध नियोजक किसी मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा और मामले के गुणात्मक को ध्यान में रखते हुए विकास अधिकारी को अनुतोष अंजूर कर सकता, तरीका, यदि विनाम अधिकारी केन्द्रीय वर्ष में व्यवसीमा का अनुपात करते में केवल ग्रामीण भागवान के कारण नियम 11 के फायदे का महादार नहीं है ।

परन्तु यह तब जबकि वह अनुपात जो केन्द्रीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में व्यवसीमा के विवरण के अनुसार सुसंगत वर्षों के व्यय सीमा से अधिक नहीं है ;

परन्तु यह और कि विनाम अधिकारी को तब तक उपलब्ध होता जब वह नियम 11 के अधीन स्वयं को अर्हित कर लेंगा ।

(2) प्रबंध नियोजक, जोन प्रबंधक की मिकारिय पर, अन्वेषणा सारणी के अनुसार मूल बेतन में कमी की तारीख के पश्चात् किसी विकास अधिकारी के किसी मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा यदि वह

नियम 13 या नियम 14 के अधीन पुनः स्थापन के लिए प्रहृत नहीं करता है और भासले के गुणात्मकों को व्याप में रखते हुए ऐसा अनुसूचि प्रदान कर सकेगा किन्तु उस अनुसूचि से अधिक नहीं होगा जो उसे तब अनुज्ञय होता जब वह पुनः स्थापन के लिए उप्रति नियमों में से किसी के अधीन स्थापन को अद्वित करता।

17. प्रेरणा :

नियम द्वारा अनुसूचित किसी स्कीम के अधीन प्रेरणा जोनल किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी को तब मंजूर की जा सकेगी जब उस वर्ष में उसके वार्षिक पारिश्रमिक के प्रति नियम से लागत अनुपात उस वर्ष के आदेश श्रीमियम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

18. विकास अधिकारी की प्रोत्तिः

यौथ भवनों जाने वाले किसी भी विकास अधिकारी की प्रोत्ति कर्मचारिवृत्त नियमों के नियम 7 के अनुसार सहायक शास्त्रा प्रबंधक या सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में की जा सकती है।

19. सेवा -समाप्त विकास अधिकारी की पुरुनियुक्ति :

यदि किसी ऐसे विकास अधिकारी ने जिसकी सेवाओं को नियम 8 के अनुसरण में समाप्त किया गया है, ऐसी सेवा समाप्ति की तारीख को वर्ष-2 में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 55 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो वह ऐसी प्रहृत और योग्यता के अनुसार जो अधिक नियम की धारा 48 की उपचारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियन्त्रित की जाए, वर्ष-3 में प्रशासनिक कार्य करने के लिए सहायक या अधिसेक लिपिक के रूप में नियम की सेवा में पुरुनियुक्ति के लिए पात्र होगा :

प्रदत्त सेवा समाप्ति के परिणामस्वरूप सेवा में व्यवधान के होते हुए भी नियम में उसकी सेवा सुधारी के प्रयोजन के लिए निरन्तर मानी जाएगी और उपचारा या अधिक्षय नियम के प्रयोजन के लिए भी यदि उसने वह प्राप्त नहीं की है और यदि उसने प्राप्त की है किन्तु वह नियम को उपचार या अधिक्षय नियम की ऐसी रकम का सवाय करता है तो उसमें प्राप्त की है।

20. नियत भौर व्यावृत्ति

(1) कर्मचारीवृत्त नियम की अनुसूची 3 भौर जीवन वीमा नियम विकास अधिकारी (पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निवंधनों सहा शर्तों का परिवर्तन) आवेदन, 1978 ऐसी बातों के सिवाएँ निरसित किया जाता है जो कर्मचारीवृत्त नियम की अनुसूची 3 के अधीन की गई है या किए जाने से क्षेत्र की गई है और जीवन वीमा नियम विकास अधिकारी (पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निवंधनों तथा शर्तों का परिवर्तन) आवेदन, 1978 भी नियसित किया जाता है।

(2) इन नियमों की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह कर्मचारिवृत्त नियमों के अनुसार किसी विकास अधिकारी को सेवानिवृत्त करने या उसकी सेवाओं को अवधारित करने के संबंधमें प्राधिकार प्रभाव डालता है या कर्मचारिवृत्त नियमों के नियम 39 के अधीन उसमें विनियोगित किन्हीं आधारों पर उस पर कोई शास्त्र अधिरोपित करने के अनुकूल शान्तिक प्राधिकारी के अधिकार को प्रभावित करती है या ऐसे मामलों की आवत जो इन नियमों में उल्लिखित नहीं हैं विकास अधिकारियों के कर्मचारीवृत्त नियमों पर लागू होती है।

21. निर्विचार

जहाँ इन नियमों के नियन्त्रण की आवत कोई संदेह या कठिनाई पैदा होती है वहाँ वह विनियोग के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्विचित की जाएगी।

[फा. सं. 2(60)/वीमा. III/86]

एन. आर. रंगनाथन, अपर सचिव

स्टार्टिकारक टिप्पणी :

केन्द्रीय सरकार ने 1 मार्च 1988 से भारतीय जीवन वीमा नियम के विकास अधिकारियों की सेवा के कुछ निवंधनों और शर्तों को पुनरीक्षित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। लदनुसार नियमों को 1 मार्च 1988 से भूतलधी प्रभाव दिया गया है।

2. यह प्रभागित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से जीवन वीमा नियम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पहुँचने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 1989

INSURANCE

Life Insurance Corporation of India
(Department of Economic Affairs)
Terms and Conditions of
Service) Rules, 1989.

G.S.R. 643(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (cc) of sub-section (2), of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules regulating certain terms and conditions of service relating to business performance of Development Officers of the Life Insurance Corporation of India, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1988.

2 Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) “Act” means the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) ;

(b) “ad hoc annual remuneration” means the yearly remuneration applicable to a Development Officer for the purpose of disincentives, computed in the manner set forth in clause (i) of the Explanation to sub-rule (1) of rule 7 ;

(c) “annual remuneration” means the basic pay, special pay, personal pay, dearness allowance, and all other allowances and non-profit sharing or ex-gratia bonus due to or paid to, a Development Officer during the appraisal year and includes the expenses payable or reimbursed to him or incurred by the Corporation during that year in respect of travelling, residential telephone and insurance premium and taxes on motor vehicles, but does not include incentive bonus and additional conveyance allowance paid to him in accordance with rules 17 ;

- (d) "appraisal date" means—
- (I) in relation to a Development Officer appointed on or after the 1st day of April, 1988,
- (A) in the first year of his service the first day of the month following that in which he completes twelve months of service from the date of his appointment, and
- (B) in every subsequent year of his service, the first day of the month following that in which he completes twelve months of service from the last appraisal date;
- (II) in relation to a Development Officer appointed prior to the 1st day of April, 1988,
- (A) in the first year of his service from 1st April, 1988,—
- (i) 1st April, 1988 if he has completed twelve months of service as on 31st March, 1988; or
- (ii) the 1st day of the month following that in which he completes a further period of twelve months of service from the date on which his last annual increment accrued (whether released or not) in accordance with sub-rule (2) of rule 50 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, if he had completed twelve months of service or more prior to 1st March, 1988; and
- (B) in every subsequent year of service, the first day of month following that in which he completes twelve months of service from the last appraisal date;
- (e) "appraisal year" means the period between two consecutive appraisal dates; and the period of twelve months of service preceding the appraisal date ascertained in accordance with item (A) of sub-clause (I), and each period of twelve months of service next preceding the appraisal date ascertained in accordance with item (A) of sub-clause (II) of clause (d), shall also be an appraisal year;
- (f) "cost ratio" in relation to a Development Officer means the ratio which his annual remuneration in any year, or his ad hoc annual remuneration, if applicable, bears to the eligible premium of that year and expressed as a percentage of such eligible premium;
- (g) "decrement" means reduction in basic pay by one or more stages in the scale of pay on one or more occasions;
- (h) "Development Officer" means a whole-time salaried employee of the Corporation belonging to Class II appointed as Development Officer and includes any person who became an employee of the Corporation on the 1st day of September, 1956 and is working as a Development Officer;
- (i) "disincentive" means reduction in conveyance allowance or non-grant of increment or decrement as provided in the "Table of Disincentives";
- (j) "eligible premium" means such proportion as may be specified by the Corporation from time to time of the first year's premiums received by the Corporation in respect of the business secured by the agents in the organisation of a Development Officer which is adjusted in the relevant appraisal year;
- (k) "expense limit" in respect of an appraisal year in relation to a Development Officer working in an operational area specified in column (1) of the Table below (hereinafter referred to as the "Table of Expense Limit") means the percentage of the eligible premium of that year as specified in the corresponding entry in column (2) thereof:

TABLE OF EXPENSE LIMIT

If the Development Officer is working in operational area	Percentage of the eligible premium
(1)	(2)
A	22%
B	23%
C	24%
D	25%
E	26%

Note : The expense limit of a Development Officer for any appraisal year is expressed as a percentage of the eligible premium of that year; a Development Officer is said to exceed the expense limit if his annual remuneration in that year is in excess of the expense limit; such excess or the ratio which such annual remuneration bears to the eligible premium of that year may also be expressed as a percentage of the eligible premium;

- (l) "operational area" with reference to a Development Officer means the area in which he is posted to work as such Development Officer and a Development Officer is said to be working in operational area—
- 'A' if he is working in a City, Urban agglomeration or Town with an ascertained population of more than 10 lakhs;
- 'B' if he is working in a City, Urban agglomeration or Town with an ascertained population of 4 lakhs or above but not more than 10 lakhs;

'C' if he is working in a City, Urban agglomeration or Town (not being a rural area or a deep rural area) with an ascertained population of less than 4 lakhs;

'D' if he is working in a rural area; and

'E' if he is working in a deep rural area or any hilly area specified in Explanation (4) or any other hilly area which the Central Government may in consultation with the Corporation by notification in the Official Gazette specify in this behalf.

Explanation : For the purposes of this clause,—

- (1) "ascertained population" means the population as ascertained from the latest Census Report of the Government of India;
- (2) a Development Officer is said to be working in a "rural area" if his headquarters is at a place with an ascertained population of 30,000 or less and his operational area has an ascertained population of not more than one lakh;
- (3) a Development Officer is said to be working in a "deep rural area" if his headquarters is at a place with an ascertained population of 10,000 or less and his operational area has an ascertained population of not more than 60,000;
- (4) a Development Officer is said to be working in a "hilly area" if his headquarter is at a place situated at a height of 1000 metres and over, above mean sea level, with an ascertained population of 20,000 or less and his operational area has an ascertained population of not more than 75,000;
- (m) "preceding year" or "relevant appraisal year" means the appraisal year immediately preceding the relevant appraisal date;
- (n) "prescribed expense limit" or "prescribed cost ratio" means the increased expense limit ascertained in accordance with proviso to sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 4, where such expense limit is applicable to a Development Officer, or if it is not so applicable to him, the expressions shall mean the expense limit applicable to him;
- (o) "relevant appraisal date" means the appraisal date on which the performance of the Development Officer for the appraisal year immediately preceding that date is assessed for any purpose under these rules or was assessed hitherto under the staff rules;
- (p) "service" means the period spent on duty as a Development Officer and leave including extraordinary leave which has been condoned under Rule 69(4) of staff rules;
- (q) "staff rules" means the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960;
- (r) "succeeding year" means the period of twelve months commencing from the relevant appraisal date;

(s) "Table of Disincentives" means the Table below sub-rule (1) of rule 7;

(t) "Table of Increased Expense Limit" means the Table below sub-rule (2) of rule 4;

(u) words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the staff rules shall have the meanings assigned to them in the staff rules.

3. Tenure :

Subject to the provisions of these rules, a Development Officer shall hold office by the same tenure and in the same manner as any other class of employee in the Corporation¹

Provided that he shall conform to the expense limit applicable to him:

Provided further that the services of a confirmed Development Officer shall not be terminated on the ground of poor business production resulting in cost ratio in excess of the expense limit applicable to him, unless he has been given an opportunity to conform to the expense limit as provided in rule 7.

4. Expense limit applicable to Development Officers :

(1) The expense limit applicable to a Development Officer shall be as specified in the Table of Expense Limit :

Provided that where a Development Officer has put in more than ten years of service as a Development Officer at the Commencement of the relevant appraisal year, the expense limit applicable to him for the relevant appraisal year shall be the expense limit applicable to his operational area as increased by one percent, if, at or before such commencement of the relevant appraisal year, he has completed 50 years of age and such expense limit shall be increased by two percent if he has completed 52 years of age by three percent, if he has completed 54 years of age with effect from the 1st day of October, 1987.

(2) Where the equitable relief granted to a Development Officer forms part of his annual remuneration in pursuance of the provisions contained in rule 10 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, the expense limit applicable to him for the appraisal years specified in column (1) of the Table below shall be the expense limit as increased with effect from the 1st day of October, 1987, by the percentage specified in the corresponding entry in column (2) thereof:

Table of Increased Expense Limit

Appraisal years commencing on the first day of any of the twelve months in the following blocks	Percentage

(1)	(2)
(a) October, 1986—September, 1987	2%
(b) October, 1987—September, 1988	2%
(c) October, 1988—September, 1989	1%

(3) The increased expense limit specified in the proviso to sub-rule (1) and sub-rule (2) shall apply to appraisals due on the relevant appraisal date falling on or after 1st October, 1987 in respect of operational areas 'A', 'B', 'C' and 'D':

Provided that in respect of appraisals due on the relevant appraisal dates falling on or after 1st October, 1987 but before 1st April, 1988, the opportunity to conform to the expense limit shall be regulated in accordance with the Table below paragraph 5 in Schedule III of the staff rules as in force at the relevant time.

(4) The increased expense limit specified in the proviso to sub-rule (1) and sub-rule (2) shall apply to appraisals due on the relevant appraisal date falling on or after 1st April, 1988 in respect of operational area 'E'.

(5) Notwithstanding anything contained in the proviso to sub-rule (1) or sub-rule (2) the percentages specified in column (2) of the Table of Disincentives or the percentages specified in sub-rule (8) of rule 7 shall not be increased.

5. Increments :

(1) Increments shall ordinarily be drawn by a Development Officer as a matter of course in accordance with rule 56 of the staff rules, unless he has reached the maximum of the grade or the increment cannot be allowed in accordance with rule 7 or rule 10 or it is withheld as a disciplinary measure under rule 39 of the staff rules.

(2) Where no increment is granted to a Development Officer in any year in accordance with rule 7 as a disincentive, such increment shall not be granted to him in any subsequent year except in accordance with the provisions contained in rule 9.

6. Conveyance Allowance :

Every Development Officer shall be entitled to such conveyance allowance as may be granted by the Corporation from time to time:

Provided that the conveyance allowance admissible to a Development Officer in any year shall be subject to the provisions of rule 7

7. Opportunity to conform to the expense limit :

(1) Where the annual remuneration of any Development Officer in the preceding year or years is in excess of the expense limit, his services shall not be terminated merely on that ground if his case is capable of being dealt with by awarding disincentives, subject to the provisions of rule 9, from the relevant appraisal date as provided in the Table of Disincentives, so as to afford him opportunity to conform to the expense limit .

Provided that for the purpose of award of disincentives in accordance with the Table of Disincentives his performance shall be appraised with reference to the ad hoc annual remuneration and the prescribed;

TABLE OF DISINCENTIVES

Sl. No. Where ad hoc annual remuneration is in excess of the prescribed expense limit or cost ratio is in excess of prescribed limit in the appraisal year next preceding the appraisal date.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	On the first occasion	On the second successive occasion	On the third successive occasion	On the fourth successive occasion	On the fifth successive occasion
(A) By not more than 2% (provided that the cost ratio in the appraisal years is not more than 35%)		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL					
(2) By more than 2% but not more than 6% (provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 35%)		30% cut in CA	50% cut in CA	60% cut in CA	60% cut in CA and no increment	80% cut in CA and no increment					
(3) By more than 6% but not more than 9% (provided the cost ratio in the appraisal year is not more than 35%)		50% cut in CA	60% cut in CA and no increment	60% cut in CA and no increment	80% cut in CA and no increment	80% cut in CA and no increment					
(4) By more than 9% (provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 35%)		60% cut in CA and no increment	60% cut in CA and no increment	80% cut in CA and no increment	80% cut in CA and one decrement	80% cut in CA and one decrement					

1	2	3	4	5	6	7
(5) Where the cost ratio in the appraisal year is more than 35% but not more than 40%	60% cut in CA and no increment and no increment and one decrement	60% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement.
(6) Where the cost ratio in the appraisal year is more than 40%	60% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement.

Note: For the purposes of this Table :—

- (a) "cut in CA" means reduction in Conveyance Allowance;
- (b) "no increment" means non-grant of increment;
- (c) "decrement" means reduction in basic pay by one stage.

Explanation : For the purposes of this sub-rule,—

(i) (a) The ad hoc annual remuneration for the purpose of appraisal for award of disincentive shall be formally ascertained and shall be deemed to be twelve times of the basic pay, special pay, personal pay, separate pay, dearness allowance and all other allowances including conveyance allowance admissible to a Development Officer on the first day of the appraisal year preceding the relevant appraisal date and non-profit sharing or ex-gratia bonus due or paid to him during the appraisal year as also the total expenses payable or reimbursed to him or incurred on him or due in respect of travelling, residential telephone and insurance premium and taxes on motor vehicles :

Provided that if his conveyance allowance has been increased during the preceding year either as a consequence of his acquiring a vehicle or switching to a different type of vehicle or by reason of any revision of conveyance allowance, the increased conveyance allowance paid to him during the year shall be added to arrive at the ad hoc annual remuneration applicable to him.

(b) The method of computing the ad hoc annual remuneration in the foregoing manner shall govern all appraisals due on the relevant appraisal date falling on or after 1st April, 1988, for the purpose of disincentives :

Provided that for the appraisals due on the relevant appraisal dates which may fall on or after 1st April, 1989, if the ad hoc annual remuneration for the preceding year (hereafter in this sub-clause referred to as the "relevant year") computed in the manner specified in sub-clause (a) exceeds the ad hoc annual remuneration computed in the same manner for the appraisal year next preceding the relevant year by more than 10 per cent, the ad hoc annual remuneration for the relevant year shall be deemed to be 110% of the ad hoc annual remuneration computed in accordance with sub-clause (a) for such appraisal year next preceding the relevant year :

Provided further that if the conveyance allowance of the Development Officer has been increased during the relevant year either as a consequence of his acquiring a vehicle or switching over to a different

type of vehicle or by reason of any revision of conveyance allowance, the increased conveyance allowance paid to him during the year shall be added to the amount computed in accordance with the preceding proviso to arrive at his ad hoc annual remuneration.

(c) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) or sub-clause (b), where a Development Officer has put in more than ten years of service as a Development Officer and has completed 55 years of age at the commencement of the relevant appraisal year, his performance shall be appraised for the purpose of award of disincentives with reference to the annual remuneration applicable to him as formally ascertained for the appraisal year at the commencement of which he has fulfilled the requirements specified in this clause and such annual remuneration shall be deemed to be the ad hoc annual remuneration also in his case :

Provided that in respect of a Development Officer who had fulfilled the requirements as to the aforesaid service and age on a date prior to 1st April, 1988, or at or before the commencement of any appraisal year, the ad hoc annual remuneration shall be deemed to be the annual remuneration applicable to him as formally ascertained in the relevant appraisal year commencing on or after 1st October, 1986:

Provided further that if the conveyance allowance of the Development Officer has been increased in any subsequent year either as a consequence of his acquiring a vehicle or switching over to a different type of vehicle or by reason of any revision of conveyance allowance, the increased conveyance allowance paid to him shall be added to the amount computed in accordance with the preceding provisions to arrive at his ad hoc annual remuneration in such subsequent year and thereafter.

(d) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses, if the annual remuneration of Development Officer in any appraisal year was less than the ad hoc annual remuneration computed in the manner specified above, such annual remuneration shall be deemed to be the ad hoc annual remuneration applicable to him in that appraisal year for the purpose of appraisal for award of disincentives.

(e) Where the scales of pay or allowances are altered in pursuance of any rules relating to general revision of the terms and conditions of service of Development Officers, the computation of the ad hoc annual remuneration under the foregoing sub-clauses shall be subject to the provisions of such rules issued under Section 48 of the Act.

(f) The computation of ad hoc annual remuneration in term of this clause shall be for the purpose of disincentives only and for all other purposes the annual remuneration shall be taken into account.

(g) For the purposes of clause (i) of this Explanation, the remuneration shall be formally ascertained by calculating or computing the remuneration to which the employee is eligible under these rules in the normal course, without taking into account any deduction, reduction or withholding of any part of the remuneration under special circumstances, such as suspension, extraordinary leave or sick leave on half-pay, or for any other reasons.

(ii) The application of the Table of Disincentives shall be subject to the provisions contained in rule 9 provided the services of the Development Officer are not liable to be terminated under sub-rule (2) or sub-rule (8) of this rule.

(iii) For the purpose of the Table of Disincentives, the ad hoc annual remuneration of a Development Officer shall be deemed to be in excess of the prescribed expense limit on a successive occasion if such remuneration exceeds such expense limit in two consecutive appraisal years even though the excess percentage over the prescribed expense limit may vary and an appraisal year in which the Development Officer exceeds the prescribed expense limit even though there is no disincentive shall also be reckoned for ascertaining whether the expense limit is exceeded on successive occasions and the disincentive on the successive occasion shall correspond to the excess of the prescribed expense limit in the appraisal year next preceding the relevant appraisal date.

(iv) The Table of Disincentives shall be necessarily applied, if, after conforming to the prescribed expense limit, the Development Officer exceeds it again at a later date.

(2) If, as a consequence of the application of the provisions contained in sub-rule (1) the basic pay arrived at falls below the minimum of the grade applicable to the Development Officer, his basic pay shall be fixed at such minimum :

Provided that the fixation of basic pay at minimum under this sub-rule shall not be allowed more than once during the entire service of a Development Officer and if, on a second occasion, the basic pay so arrived at falls below such minimum his services shall be liable to be terminated in accordance with rule 8.

(3) (a) Where the basic pay of a Development Officer is reduced or fixed under sub-rule (1) or sub-rule (2) (hereafter referred to as "revised basic pay") he shall be allowed only such allowances and other benefits as are admissible to him on that basic pay;

(b) Where his conveyance allowance has been reduced, he shall only be entitled to the conveyance allowance as so reduced on the basis of the revised basic pay:

Provided that there shall be no protection of the annual remuneration either by granting a personal allowance or otherwise; and no arrears of pay or any allowance for the past period consequent on his conforming to the expense limit later on shall be payable.

(4) The appointing authority shall be the competent authority for implementing the provisions of sub-rules (1), (2), (3) and it shall determine the matters specified in the said sub-rules, as soon as may be, after the expiry of the relevant appraisal year :

Provided that the competent authority concerned shall, before deciding any matter under this rule, give an opportunity to the Development Officer to make a representation.

(5) Where the representation received under proviso to sub-rule (4) discloses,—

(a) any actual inaccuracies in the computation of eligible premium or other figures, the competent authority shall revise his decision to the extent it is warranted by the revised figures and pass appropriate orders disposing of the representation;

(b) any cause beyond the control of the Development Officer, such as accident or sickness to justify relaxation of the expense limit and he pleads that the award of disincentives should not be effected on that ground, the competent authority shall forward the representation to the Zonal Manager, for decision.

(6) If the Zonal Manager is satisfied that there is any merit in the representation, he may consider the circumstances of the case and pass such orders as he may think fit.

(7) A Development Officer whose representation has been rejected by the Zonal Manager may submit a memorial to the Chairman in respect of that matter.

(8) Notwithstanding any thing contained in the foregoing provisions of this rule, where the ad-hoc annual remuneration of a Development Officer in any preceding year (hereafter in this sub-rule referred to as the "relevant year") exceeds 50 per cent of the eligible premium of that year and the aggregate of the ad hoc remuneration in the relevant year and the two appraisal years immediately preceding the relevant year exceeds 50 per cent of the aggregate of the eligible premium in those three years, his services shall be liable to be terminated in accordance with rule 8.

8. Termination of service in certain cases :

(1) Where a Development Officer has failed to conform to the expense limit and where no opportu-

nity to conform to such limit could be given under the provisions of rule 7, the Zonal Manager may terminate his services after giving him three months' notice or salary in lieu thereof :

Provided that the Development Officer shall be given an opportunity to show cause against the proposed termination of his services.

(2) An appeal against an order passed under sub-rule (1) shall lie to the Managing Director and the provisions of rule 41, 42, 43, 44 and 45 of the staff rules shall, so far as may be, apply to any such appeal.

(3) In the case of an appeal under sub-rule (2) the Managing Director shall consider the records of the case and pass orders on merits having regard to the circumstances of the case.

9. Deferment of Disincentives :

(1) The disincentives, other than "no increment", shall not be awarded from the relevant appraisal date (hereinafter referred to as "the relevant due date"), but shall be kept in abeyance until after the expiry of the succeeding year, if, in any preceding year a Development Officer, who has completed at least five years of service, has exceeded the prescribed expense limit attracting disincentives in accordance with the Table of Disincentives .

Provided that he has not exceeded the prescribed expense limit for a continuous period of not less than five years immediately preceding such relevant appraisal year or, where he has not completed five years of service but has completed at least three years of service and has not exceeded the prescribed expense limit in any year from the date of his joining as Development Officer.

(2) Where the Development Officer conforms to the prescribed expense limit in the succeeding year, referred to in sub-rule (1), no action shall be taken to award the disincentives which have been kept in abeyance, and if the increment, which would have otherwise accrued to him on the relevant due date, had been disallowed as a disincentive, such increment shall be released from the relevant due date.

(3) Where the Development Officer exceeds the prescribed expense limit in such succeeding year, the disincentives which have been kept in abeyance shall be awarded from the relevant due date and appropriate recovery of the excess remuneration paid to him in such succeeding year shall be made from his salary for the following year and the disincentive if any of "no increment" shall become final and he shall also be liable for action in accordance with the Table of Disincentives for his failure to conform to the prescribed expense limit in such succeeding year.

(4) Where the disincentives are not enforced or the increment is released from the relevant due date in accordance with sub-rule (2), the preceding year under sub-rule (1) will not be regarded as a year in which he has not exceeded the prescribed expense

limit for the purpose of computing the continuous service of five years or three years, as the case may be, in which he has not exceeded the prescribed expense limit.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if a Development Officer is at a stage where there is an efficiency bar, no increment shall be granted to him above that bar unless he has satisfied the requirements of rule 10.

10. Efficiency Bar :

(1) Where there is an efficiency bar in a scale of pay, a Development Officer shall not be certified fit to draw increments above that bar on or after 1st April, 1988, unless,—

(a) his cost ratio with reference to his annual remuneration was not in excess of 20% in the appraisal year immediately preceding the relevant appraisal date (hereafter in this sub-rule referred to as the "relevant year");

(b) he has not exceeded the expense limit applicable to him in the two appraisal years immediately preceding the relevant year.

(2) Where a Development Officer is allowed to cross an efficiency bar which has previously been enforced against him, he shall be allowed only one increment from a prospective date .

Provided that more than one increment may be allowed on removal of efficiency bar if he becomes eligible for any increment in accordance with rule 11, 12, 13 or 14.

(3) Where a Development Officer has crossed an efficiency bar but has been brought below that efficiency bar for any reason whatsoever, he may be allowed to cross that efficiency bar when he becomes eligible for his next increment, unless his increment has been withheld as a disciplinary measure under rule 39 of the staff rules.

11. Prospective restoration of reduction in basic pay in pursuance of Schedule III to the staff rules prior to the relevant appraisal date falling on or before 31-3-1988 :

(1) Where a Development Officer has conformed to the expense limit in the appraisal years relevant to the appraisal dates falling before 1st April, 1988 in the manner specified in this rule and he continues to conform to the expense limit thereafter, the reduction in his basic pay effected after 20th day of June, 1979, on the ground that he had exceeded the expense limit in any appraisal year in respect of which the relevant appraisal date was falling on or before 31st March, 1988 (such reduction in basic pay being hereinafter referred to as "past decrements") may be restored in accordance with the provisions of sub-rule (3) :

Provided that where a Development Officer qualifies for restoration of past decrements, the past de-

rement which was first effected as a result of appraisal falling on the appraisal date subsequent to 20th day of June, 1979 shall first be restored, the past decrement which was effected thereafter shall be restored next and so on.

Explanation : For the purposes of this sub-rule, a past decrement pertaining to a year may consist of one stage or more than one stage in the scale of pay.

(2) The benefit of this rule shall accrue to a Development Officer only if he has conformed to the expense limit in the appraisal year immediately preceding the appraisal date falling on or after 1st day of April, 1987 but before the 1st day of April, 1988 (hereinafter referred to as the "central years") and the two appraisal years immediately preceding the central year and he shall continue to be eligible for the benefit of this rule so long thereafter as he conforms to the expense limit in the successive appraisal years next following the central year in chain and if the chain is interrupted by an appraisal year in which he fails to conform to the expense limit, he shall cease to get the benefit under this rule on and after the appraisal date relevant to such appraisal year.

Explanation : For the purpose of this rule, "chain" means a chain of three or more uninterrupted appraisal years in which the Development Officer has not exceeded the expense limit :

Provided that the appraisal year next following the central year or any appraisal year thereafter may be reckoned for the purpose of the said successive appraisal years if the cost ratio of the Development Officer in such appraisal year is not in excess of the expense limit by more than 2%.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4) and sub-rule (5) :—

(i) where a Development Officer conforms to the expense limit on the first appraisal date falling on or after 1st April, 1987 in the central year and has to his credit a combined chain of three years the past decrements pertaining to one year may be restored from such first appraisal date.

Explanation : For the purposes of this sub-rule, "combined chain of three years", in relation to a Development Officer, means the central year and two appraisal years immediately preceding it in which he has conformed to the expense limit;

(ii) if, besides a combined chain of three years, the Development Officer has to his credit a rear chain of three years or more than one such rear chain, the past decrements pertaining to as many years as there are rear chains of three years may be restored with effect from the first appraisal date referred to in clause (i);

Explanation : For the purposes of this sub-rule, "rear chain of three years", in relation to a Development Officer, means the appraisal year immediately preceding the central year and other uninterrupted

appraisal years preceding such appraisal year in chain in which a Development Officer has conformed to the expense limit;

(iii) if the Development Officer has acquired to his credit a combined chain of three years but the past decrements cannot be restored in the absence of a rear chain of three years or the requisite number of such rear chains, and, if, on the relevant appraisal date relating to the appraisal year next following the central year, a special chain accrues to his credit, the eligible past decrements, if any, may be restored from such relevant appraisal date subject to the condition that where the reduction in basic pay pertaining to one year consists of more stages than one in the scale of pay, no restoration of eligible past decrement, shall fall due unless the prospective cost supports at least one stage in the scale of pay, but a Development Officer may qualify for restoration of the remaining stages of the reduction in basic pay pertaining to that year on the next occasion and on that occasion such remaining stages shall be deemed to be reduction in basic pay pertaining to one year.

Explanation : For the purposes of this sub-rule,—

- "special chain", in relation to a Development Officer means the central year and the appraisal year immediately preceding and succeeding the central year in which a Development Officer has conformed to the expense limit;
- "eligible past decrement" means the reduction in basic pay by one or more stages effected in one year, which or part of which, if restored, shall keep the prospective cost within ceiling;
- "prospective cost" means the ratio which the annual remuneration applicable to a Development Officer on the relevant appraisal date (inclusive of all increments and proposed restoration on and from that date) bears to the eligible premium of the preceding year and the prospective cost shall be deemed to be within ceiling if such annual remuneration applicable to a Development Officer is not in excess of his expense limit percentage of such eligible premium;
- "restoration" means the restoration of past decrement (by whatever name called).
- if any past decrements still remain to be restored after following the provisions of clauses (i) to (iii), further eligible past decrement for the relevant chain of three years may be restored from each of the respective appraisal dates on which he acquires a retro-progressive chain to his credit.

Explanation : For the purposes of this sub-rule,—

- (a) “retro-progressive chain” in relation to any period beginning with the central year, means a chain of three years reckoned backwards from the relevant appraisal date to the beginning of the central year in which a Development Officer has conformed to the expense limit;
- (b) “relevant chain of three years” means the chain of three years immediately preceding the relevant appraisal date which only shall be considered for the purpose of restoration of eligible past decrement on that date.

(4) If the Development Officer is at a stage in the scale of pay where there is an efficiency bar, no restoration shall be allowed unless he is eligible for crossing the efficiency bar in accordance with rule 10 in the appraisal year immediately preceding the appraisal date on which he may otherwise qualify for restoration.

(5) No restoration shall be allowed if, on restoration, the Development Officer shall reach a stage in the scale of pay which he would not have reached on the ground that he had exceeded the expense limit, and in such a case the restoration shall be limited to the stage in the scale of pay which he would have normally reached.

12. Prospective restoration of reduction in basic pay effected in pursuance of Schedule III to the staff rules prior to the relevant appraisal date falling on or before 31-3-1988—Alternative method :

(1) Subject to sub-rule (4) and sub-rule (5) of rule 11, if the cost ratio of a Development Officer does not exceed 15 per cent in the first or the second or the third appraisal year preceding the relevant appraisal dates falling on or after 1st April, 1989, but before 31st March, 1992, past decrements pertaining to one or more years in relation to appraisal dates falling on or before 31st March, 1988 may be restored in the manner specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 11, from the relevant appraisal dates to the extent the prospective cost remains within ceiling :

Provided that if the Development Officer is also eligible for any restoration in accordance with rule 11, he may opt for restoration either under that rule or this rule.

(2) For the purposes of this rule, the expressions “past decrements”, “restoration” and “prospective cost” shall have the same meaning as assigned to them in rule 11.

13. Reinforcement of reduction in basic pay effected in accordance with the Table of Disincentives as a result of appraisal where the relevant appraisal date falls on or after 1-4-1988 :

(1) The reduction effected in the basic pay of a Development Officer as a result of appraisal on the relevant appraisal date falling on or after 1st April,

1988 (hereinafter referred to as “current decrements”) may be reinstated in accordance with the provisions of this rule or rule 14.

(2) Where a Development Officer qualifies for reinstatement in accordance with this rule, the reduction in basic pay which was first effected on or after 1st April, 1988 shall first be reinstated; the reduction in basic pay which was effected thereafter shall be reinstated next and so on .

Provided that if a Development Officer fails to qualify for reinstatement within five appraisal years following the appraisal date from which his basic pay was reduced, there shall be no reinstatement of that reduction, and in that case the next reduction, if any, in basic pay shall be regarded as due for reinstatement if he subsequently qualifies for reinstatement :

Provided further that the reinstatement of reduction in basic pay under this rule and rule 14 shall be limited to only three occasions throughout the service as a Development Officer.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4), if on any relevant appraisal date falling on or after 1st April, 1988, the appraisal discloses that a Development Officer has not exceeded the expense limit in the preceding year and that the cost ratio in such preceding year and the next two preceding years taken together does not exceed the combined expense limit for those three years (hereinafter referred to as a “block of three years”) the eligible current decrement may be reinstated with effect from the relevant appraisal date :

Provided that in any preceding year, a Development Officer does not conform to the expense limit, he may qualify for reinstatement if there arises a block of three years on any subsequent relevant appraisal date :

Provided further that current decrement pertaining to not more than one year shall be reinstated on one relevant appraisal date, even though the future cost may support reinstatement of decrements in excess of one year.

Explanation : For the purposes of this rule,—

- (i) “block of three years” means every preceding year in which the Development Officer has not exceeded the expense limit and the next two preceding years;
- (ii) “eligible current decrement” means the current decrement pertaining to one year which if reinstated shall still keep the future cost within ceiling;
- (iii) “future cost” means the ratio which the annual remuneration applicable to a Development Officer on the relevant appraisal date (inclusive of all increments and proposed reinstatement on and from that date) bears to the eligible premium of the preceding year and the future cost shall be

deemed to be within ceiling, if such annual remuneration applicable to a Development Officer is not in excess of his expense limit percentage of such eligible premium.

(4) The provisions of sub-rule (4) and sub-rule (5) of the rule 11 shall, so far as may be, apply to reinstatement of reduction in pay as they apply to restoration of such reduction.

14. Reinstatement of reduction in basic pay effected in accordance with the Table of Disincentives as a result of appraisal where the relevant appraisal date falls on or after 1-4-1988. Alternative method :

Subject to the provisions of sub-rules (2) and (4) of rule 13, if a Development Officer does not exceed the expense limit in three successive appraisal years, the current decrement pertaining to one year may be reinstated with effect from the relevant appraisal date next following the last such appraisal year.

15. Provident Fund .

(1) Notwithstanding anything contained in rule 8 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, where the past decrements or current decrements are restored or reinstated to a Development Officer from the relevant appraisal date in accordance with the provisions contained in rule 11, 12, 13 or 14, the Corporation shall contribute to the Provident Fund established by it (hereinafter referred to as the "Fund") a maximum amount of 8½ per cent of the aggregate of the basic pay comprised in such decrements in relation to the period for which those decrements have been restored or reinstated :

Provided that if during the period of part of the period in which the said decrements were in force, the rate at which the employer's contribution was higher than 8-1/3 per cent, the Corporation may contribute at such higher rate on that part of the basic pay pertaining to the relevant period :

Provided further that the Development Officer shall contribute to the Fund an amount equal to the contributions required of the Corporation as his additional contribution in accordance with the rules of the Fund and in such manner as he may be directed by the Corporation.

(2) The Corporation shall credit its contributions to the Fund as and when and to the extent the Development Officer makes such additional contributions under the second proviso to sub-rule (1).

(3) The contributions made by the Corporation under sub-rule (1) shall not be available for any purpose for which the employer's contributions are not available under the rules of the Fund.

(4) Nothing contained in this rule shall apply to a Development Officer who is contributing to a superannuation fund approved by the Corporation.

16. Special Cases :

(1) The Managing Director may review any case and allow such relief, having regard to the merits of the case, to the Development Officer, if the Development Officer is not entitled to the benefit of rule 11 by reason only of his failure to conform to the expense limit in the central year :

Provided that the ratio which the aggregate of the annual remuneration for the central year and the two appraisal years next preceding bears to the aggregate of the eligible premium in those years does not exceed the expense limit :

Provided further that any such relief shall not exceed the benefit that would be available to the Development Officer had he qualified himself under rule 11.

(2) The Managing Director may, on the recommendation of the Zonal Manager, review any case of a Development Officer after the date of reduction in basic pay in pursuance of the Table of Disincentives if he does not qualify for reinstatement under rule 13 or rule 14 and grant such relief, having regard to the merits of the case, but not exceeding the relief that would have been admissible to him had he qualified himself under any of the said rules for reinstatement.

17. Incentives :

Incentive bonus under any scheme approved by the Corporation may be allowed to a Development Officer for any preceding year if his cost ratio with reference to his annual remuneration in that year does not exceed twenty per cent of the eligible premium of that year.

18. Promotion of Development Officer :

Any Development Officer considered suitable may be promoted as Assistant Branch Manager or Assistant Administrative Officer, in accordance with rule (7) of staff rules.

19. Re-appointment of terminated Development Officer :

If a Development Officer, whose services are terminated in pursuance of rule 8 has completed at least ten years of service in Class II on the date of such termination and has not completed 55 years of age, he shall be eligible for re-appointment in the service of the Corporation to do administrative work in Class III either as Assistant or Record Clerk in accordance with such qualification and suitability as may be specified under clause (cc) of sub-section 2 of section 48 of the Act.

Provided that notwithstanding the break in service as a consequence of termination, his service in the Corporation shall be deemed to be continuous for the purpose of leave; and also for the purpose of gratuity or Provident Fund if he has not received or if he has received but repays to the Corporation such amount of gratuity or Provident Fund as he has received.

20. Repeal and Savings :

(1) Schedule III of the staff rules, and the Life Insurance Corporation Development Officers (Alteration of Remuneration and other Terms and Conditions of Service) Order, 1978 are hereby repealed except in respect of things done or omitted to be done under the Schedule III to staff rules and Life Insurance Corporation Development Officers (Alteration of Remuneration and other Terms and Conditions of Service) Order, 1978 as so repealed.

(2) Nothing contained in these rules shall be deemed to affect the right of the Competent Authority to discharge, retire, or determine the service of a Development Officer in accordance with the staff rules or to affect the right of the disciplinary authority to impose any penalty on him under rule 39 of staff rules on any grounds specified therein or to apply the staff rules to Development Officers in respect of matters not dealt with in these rules.

21. Interpretation :

Where any doubt or difficulty arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for its decision.

[F. No. 2(60)lIns. III/86]

N. R. RANGANATHAN, Addl. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise certain terms and conditions of service of Development Officers of the Life Insurance Corporation of India with effect from 1st April, 1988. The rules are accordingly given retrospective effect from 1st April, 1988.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.